nwda.gov.in

पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना चंबल और मालवा क्षेत्र को करेगी समृद्ध

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 17 दिसंबर को जयपुर में हुआ त्रि-पक्षीय अनुबंध

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती–कालीसिंध–चंबल नदी जोड़ो परियोजना के 'मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट' पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मुख्यमंत्री राजस्थान व केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के मध्य जयपुर में हस्ताक्षर हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की 75 हजार करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के 11 जिलों गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के 2094 गांवों में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होगी। साथ ही पेयजल एवं औद्योगिक आपूर्ति के लिए जल उपलब्ध होगा। योजना में मध्यप्रदेश में 21 बांध एवं बैराज बनाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कराए जाने कार्यों की लागत लगभग 36 हजार 800 करोड़ रुपए है।

पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना से प्रदेश के चंबल और मालवा क्षेत्र के लाखों किसानों का जीवन बदलेगा। उन्हें न केवल सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, अपितु संबंधित क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की 17 परियोजनाएं एवं राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शामिल हैं। परियोजना के क्रियान्वयन में 6.11 लाख हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल व उद्योगों के लिए लगभग 172 मि.घ.मी. जल का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

21 बांध, बैराज एवं बैलेंसिंग रिजर्वायर का होगा निर्माण

संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल परियोजना में मध्यप्रदेश से प्रारम्भ होने वाली पार्वती, कूनो, कालीसिंध, चंबल, क्षिप्रा एवं सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

परियोजना के अंतर्गत श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स में 04 बांध (कटीला, सोनपुर, पावा एवं धनवाड़ी), 02 बैराज (श्यामपुर, नैनागढ), कुम्भराज कॉम्प्लेक्स में 02 बांध (कुम्भराज–1 एवं कुम्भराज–2) तथा रणजीत सागर, लखुंदर बैराज एवं ऊपरी चम्बल कछार में 07 बांध (सोनचिरी, रामबासा, बचेरा, पदुनिया, सेवरखेडी, चितावद तथा सीकरी सुल्तानपुरा) शामिल हैं। इसके अलावा गांधी सागर बांध की अपस्ट्रीम में चंबल, क्षिप्रा और गंभीर नदियों पर छोटे–छोटे बांधों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

यह राज्य शासन की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। केन्द्र सरकार के सहयोग से बनने वाली इस परियोजना का कार्य आगामी 05 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

इस परियोजना के अंतर्गत कुल 21 बांध, बैराज एवं बैलेंसिंग रिजर्वायर आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है,साथ ही परियोजना में मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के मध्य मौजूदा चंबल दायीं मुख्य नहर (CRMC) एवं मध्यप्रदेश क्षेत्र में CRMC सिस्टम को अंतिम छोर तक नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान रखा गया है, जिससे मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिण्ड जिलों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु आवंटित जल प्राप्त हो सकेगा।

जल शक्तिमंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री और दोनों राज्यों के अपर मुख्य सचिव एवं सचिव की उपस्थिति में दिनांक 28 जनवरी 2024 को परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स की 06 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

पार्वती–कालीसिंध–चंबल नदी जोड़ो परियोजना

जन जागरण अभियान के तहत जिलों एवं ग्रामों में होंगे अनेक कार्यक्रम

- ग्रामों में मुख्य मार्गों पर कलश यात्रा एवं प्रभात फेरियां
- संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के महत्व तथा जल की आवश्यकता पर केन्द्रित नुक्कड़ नाटकों, भजन मण्डलियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- स्कूलों में जल पर केन्द्रित चित्रकला प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता
- जल संरक्षण एवं संवर्धन तथा परियोजना के लाभ से संबंधित संदेशों का दीवार लेखन।
- जन अभियान परिषद् की सहभागिता।
- जिला/जनपद/ग्रामों के जन प्रतिनिधियों, स्व–सहायता समूहों एवं स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता।
- प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायक की उपस्थिति में जिला मुख्यालय पर किसान सम्मेलनों का आयोजन। इन कार्यक्रमों में प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी

मालवा क्षेत्र के परियोजना घटकों का कार्य प्रथम चरण में होगा पूरा

संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना

भोपाल। संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत अब मालवा क्षेत्र के परियोजना घटकों का कार्य प्रथम चरण में ही किया जाएगा।

पहले इस क्षेत्र के सिंचाई एवं पेयजल प्रदाय किए जाने वाले घटकों का निर्माण फेज टू में रखा गया था। मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न बैठकों के पश्चात यह समिति बनी है। इससे मालवा क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए योजना के प्रथम चरण में ही पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाएगा।

मध्यप्रदेश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के 11 जिलों गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर तथा मुरैना के 2094 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होगी तथा पेयजल एवं औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी जल उपलब्ध होगा।

योजना में मध्य प्रदेश में 21 बांध एवं बैराज बनाए जाएंगे। योजना अंतर्गत प्रदेश में कराए जाने कार्यों की लागत लगभग पर 36 हजार 800 करोड़ रुपए है।

संशोधित पार्वती–कालीसिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना का जन जागरण अभियान

- पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस परियोजना से प्रदेश के 11 जिलों को लाभ मिलेगा।
- संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य में मालवा और चंबल क्षेत्र के 11 जिलों में 2094 ग्रामों में 6 लाख 13 हजार 520 हेक्टेयर में सिंचाई एवं 40 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा।
- लगभग 60 वर्ष पुरानी चंबल दायीं मुख्य नहर एवं वितरण तंत्र प्रणाली के नवीनीकरण/आधुनिकीकरण के कार्य से भिंड, मुरैना एवं श्योपुर के 1205 ग्रामों में 3 लाख 62 हजार क्षेत्र में कृषकों की मांग अनुसार पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

संशोधन में यह तय

पार्वती, कूनो, कालीसिंध, चंबल, क्षिप्रा एवं सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स में 4 बांध, 2 बैराज, कुंभराज कॉम्प्लेक्स में 2 बांध तथा रणजीत सागर, लखुंदर बैराज एवं ऊपरी चंबल कछार में 7 बांध शामिल हैं। गांधीसागर बांध के अपस्ट्रीम में छोटे बांधों का निर्माण भी प्रस्तावित है। परियोजना को हाल में केंद्र की मंजूरी के बाद संशोधित किया है। इस पर 75 हजार करोड़ खर्च प्रस्तावित है। मप्र के 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना के करीब 2094 गांवों में 36,800 करोड़ रुपए के काम होंगे। करीब 40 लाख परिवारों को पीने व सिंचाई का पानी मिलेगा। उद्योगों की जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना में मप्र एवं राजस्थान के मध्य मौजूदा चंबल दायीं मुख्य नहर एवं मप्र क्षेत्र में सीआरएमसी सिस्टम को अंतिम छोर तक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करने के प्रावधान किए हैं। इन कामों के पूर्ण होने के बाद श्योपुर, मुरैना, भिण्ड जिलों को भी सिंचाई व पीने का पानी मिलेगा।